*जेएस मेहंदीरत्ता*

*सतीश कुमार मित्तल और इंद्रजीत सिंह से पहले, जे जे.*

**कमल CWNUWK^-अपीलकर्ता**

*बनाम*

**एनए माननीय जांच एजेंसी-प्रतिवादी**

**सीआरए नंबर 554-DBof2012**

जुलाई3,2OI2

*राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 - एस. 21 - गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 - एस.एस. 16, 18, 43-सी और 43-0 (2)(बी) - भारतीय दंड संहिता, 1860 - एस.एस. 302, 307, 124ए, 438, 440 - रेलवे अधिनियम - धारा 150, 151 और 152 - विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 - धारा 3, 4 और 6 - सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 - धारा 3/4 - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - एस.167 - (समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस) - उस आदेश के खिलाफ अपील जिसके तहत जांच पूरी करने की अवधि 90 दिनों से बढ़ाकर*

*(सतीश कुमार मित्तल, जे.)*

***180** दिन कर दी गई थी - इस आधार पर चुनौती कि चूंकि ए ने कोई भी आरोपी नहीं बनाया था जारी किए गए*

***न ही आवेदन की सूचना दी गई और न ही आक्षेपित आदेश के पारित होने के समय वह/उसका वकील उपस्थित था, इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन नहीं किया गया है। दूसरे, समय अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती थी क्योंकि सरकारी वकील की रिपोर्ट अदालत के सामने नहीं रखी गई थी - आरोपी को नोटिस जारी करने की अनिवार्य आवश्यकता का पालन नहीं किया गया था - जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने से पहले कोई अवसर नहीं दिया गया था***

***आयोजित,***न तो आवेदन और न ही आक्षेपित आदेश यह दर्शाता है कि लोक अभियोजक ने अपने दिमाग का उचित उपयोग करने के बाद और जांच की प्रगति के बारे में संतुष्ट होने के बाद उक्त आवेदन दायर किया। यद्यपि यूए (पी) अधिनियम की धारा 43-डी (2) (बी) का प्रावधान किसी भी अदालत के समक्ष विचार के लिए नहीं आया है, लेकिन निर्विवाद रूप से, ये प्रावधान धारा की उपधारा (4) के खंड (बीबी) के लिए पैरामटेरिया हैं। TADA के 20, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त दो निर्णयों में विचार किया है। [हितेंद्र विष्णुठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य; 1994 एससीसी (आपराधिक) 1087 और संजय दत्त बनाम राज्य सीबी1, बॉम्बे (द्वितीय) के माध्यम से; (1994) 5 एससीसी 410] इसलिए, इन दो निर्णयों में दी गई व्याख्या यूए (पी) अधिनियम की धारा 43-डी (2) (बी) के प्रावधान पर पूरी तरह लागू होगी।

(पैरा 8)

***आगे आयोजित,***मौजूदा मामले में आरोपी को नोटिस जारी करने की अनिवार्य आवश्यकता का पालन नहीं किया गया। यहां तक कि 9.5.2012 को, जब जांच एजेंसी द्वारा जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया गया था और अनुमति दी गई थी, तब भी आरोपी उपस्थित नहीं था। जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने से पहले, आरोपी को उक्त का विरोध करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था। प्रार्थना। इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ। आक्षेपित आदेश से अभियुक्त पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, क्योंकि समय बढ़ाने से जमानत पर रिहाई का आदेश प्राप्त करने का उसका अपरिहार्य अधिकार समाप्त हो रहा था। जैसा कि उपरोक्त निर्णयों में दर्शाया गया है, लोक अभियोजक के माध्यम से आवेदन को आगे बढ़ाने और लोक अभियोजक की रिपोर्ट दाखिल करने की अन्य आवश्यकताओं का भी अनुपालन नहीं किया गया है।

(पैरा 9)

अपील की अनुमति.

अपीलकर्ता की ओर से वीसीनीत शर्मा, अधिवक्ता।

प्रतिवादी की ओर से सुखदीप एस. संधू, वकील।

**सतीश कुमार मित्तल, जे.**

(1) आरोपी कमल चौहान ने यह अपील राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 (एचसीआरसीआई नेलर को 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 21 के तहत एनआईए, विशेष न्यायालय, पंचकुला द्वारा पारित दिनांक

9.5.2012 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की है, जिसके तहत आवेदन दायर किया गया था। प्रतिवादी द्वारा जांच पूरी करने की अवधि को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने की अनुमति दी गई।

(2) आरोपी कमल चौहान को एनआईए केस नंबर 9, 2010 में 12.2.2012 को गिरफ्तार किया गया था, जो गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 16, 18 के तहत दर्ज किया गया था [इसके बाद 'यूए (पी) अधिनियम' के रूप में जाना जाता है] , भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 124ए, 438, 440, रेलवे अधिनियम की धारा 150, 151,152, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3,4,6 और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3/4, संबंधित समझौता एक्सप्रेस ट्रेन विस्फोट में 68 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए। जांच के दौरान, प्रारंभिक पुलिस रिमांड के बाद, आरोपी कमल चौहान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित) के तहत प्रावधानित 90 दिनों की जांच अवधि, धारा 43 के प्रावधान के साथ पढ़ी जाएगी। -यूए (पी) अधिनियम का डी (2) (बी) 11.5.2012 को समाप्त होने वाला था। 9.5.2012 को, राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इंस्पेक्टर आरएस जंबवाल के माध्यम से एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी करने और पूरक चालान दाखिल करने की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने की मांग की गई थी। आवेदन में कहा गया कि ईजी की जांच महत्वपूर्ण चरण में है और इस्तेमाल किए गए विस्फोटक की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए विभिन्न राज्यों में फैली हुई है। आगे कहा गया कि आरोपी व्यक्तियों के मध्य प्रदेश से नई दिल्ली तक के यात्रा रिकॉर्ड, नई दिल्ली में रहने से संबंधित रिकॉर्ड, बम विस्फोट से पहले/बाद में इस्तेमाल किए गए संचार के विवरण, आरोपी व्यक्ति के बैंक रिकॉर्ड को सत्यापित करने की आवश्यकता थी। यह भी कहा गया कि आरोपी के अन्य करीबी सहयोगी अपनी गिरफ्तारी से बच रहे हैं और यदि आरोपी डिफ़ॉल्ट धारा के तहत मुक्त हो जाता है, तो अन्य सह-अभियुक्त को नहीं पकड़ा जाएगा। एनआईए. विशेष न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए दिनांक 9.5.2012 को उक्त आवेदन स्वीकार कर लिया

> "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जांच प्रगति पर है और जांच देश के कई हिस्सों में फैली हुई है और जांच एजेंसी को बड़े पैमाने पर जांच करनी है
>
> रेलवे का रिकॉर्ड जो अभियोजन के अनुसार पांच साल पुराना है, आवेदन की अनुमति है और धारा 167 सीआर के तहत चालान दाखिल करने के लिए समय 180 दिनों तक बढ़ाया गया है। पीसी यूए (पी) अधिनियम की धारा 43-डी (2) (बी) के साथ पढ़ा गया।

यहां यह बताना प्रासंगिक होगा कि उक्त आवेदन की अनुमति के समय न तो अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित था और न ही उसे उक्त आवेदन का नोटिस जारी किया गया था। उपरोक्त आदेश अभियुक्त को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना पारित किया गया था।

(3) आरोपी कमल चौहान ने उपरोक्त आदेश को दो आधारों पर चुनौती दी है, पहला, जांच पूरी करने की अवधि बढ़ाने से पहले, आरोपी को नोटिस जारी किया जाना चाहिए, ताकि वह उपलब्ध सभी वैध और कानूनी आधारों पर ऐसी प्रार्थना का विरोध करने में सक्षम हो सके। उसे। वर्तमान मामले में, न तो आवेदन का नोटिस अभियुक्त या उसके वकील को जारी किया गया था, न ही अभियुक्त आक्षेपित आदेश पारित करने के समय उपस्थित था। इस प्रकार, इस मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन नहीं किया गया है, इसलिए, विवादित आदेश अवैध है और रद्द किये जाने योग्य है। दूसरे,

विद्वान वकील ने तर्क दिया कि जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने से पहले, लोक अभियोजक की रिपोर्ट अदालत के सामने नहीं रखी गई थी और ऐसी रिपोर्ट की जांच किए बिना, ट्रायल कोर्ट द्वारा समय बढ़ा दिया गया है। आगे यह तर्क दिया गया है कि जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करने वाला आवेदन लोक अभियोजक द्वारा जांच एजेंसी के अनुरोध पर अपना स्वतंत्र दिमाग लगाने के बाद दायर किया जा सकता है, लेकिन जांच एजेंसी को खुद ही समय बढ़ाने की मांग करने वाला आवेदन दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। जांच पूरी करने के लिए समय चाहिए। वर्तमान मामले में, लोक अभियोजक की रिपोर्ट दाखिल किए बिना, जांच एजेंसी द्वारा सीधे तौर पर एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे बिना दिमाग लगाए, जांच की प्रगति की जांच किए बिना और समय विस्तार देने के कारणों को प्रस्तुत किए बिना अवैध रूप से अनुमति दे दी गई थी। जांच पूरी करने के लिए. अपनी दलीलों के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील हितेंद्र विष्णु ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य (1) और संजय दत्त बनाम राज्य के माध्यम से सीबीआई, बॉम्बे (II) (2) पर भरोसा करते हैं।

(1) 1994 एससीसी (सीआरएल.) 1087

(2) (1994)5 एससीसी410

(4) हमने उपरोक्त दो मुद्दों पर पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और आक्षेपित आदेश के साथ-साथ इंस्पेक्टर आरएस जंबवाल के माध्यम से जांच एजेंसी द्वारा दायर आवेदन को भी देखा है, जिसमें जांच पूरी करने के लिए अवधि बढ़ाने की मांग की गई है।

(5) यूए (पी) अधिनियम की धारा 43-सी संहिता के प्रावधानों को जांच पर लागू करती है क्योंकि वे यूए (पी) अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं। यूए (पी) अधिनियम की धारा 43-डी की उप-धारा (2) संहिता की धारा 167 को यूए (पी) अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध से संबंधित आसानी के संबंध में लागू करती है, जो कि उप-धारा में संशोधन के अधीन है। (2), "पंद्रह दिन", "नब्बे दिन" और "साठ दिन" का संदर्भ, जहां भी वे आता है, क्रमशः "तीस दिन", "नब्बे दिन" और "नब्बे दिन" के संदर्भ के रूप में माना जाएगा; और लोक अभियोजक की रिपोर्ट से संतुष्ट हैं।

खंड (बी) के परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा गया:

> ''बशर्ते कि यदि नब्बे दिनों की उक्त अवधि के भीतर जांच पूरी करना संभव नहीं है, तो अदालत जांच की प्रगति और हिरासत के विशिष्ट कारणों का संकेत देने वाली लोक अभियोजक की रिपोर्ट से संतुष्ट हो तो ऐसा कर सकती है। अभियुक्त नब्बे दिनों की उक्त अवधि से परे, उक्त अवधि को एक सौ अस्सी दिनों तक बढ़ा सकता है।

'नमस्कार, उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, यदि जांच एजेंसी के लिए आवेदन पर नब्बे दिनों के भीतर जांच पूरी करना संभव नहीं है, तो अदालत, लोक अभियोजक की प्रगति का संकेत देने वाली रिपोर्ट से संतुष्ट होने के बाद, जांच और आरोपी को नब्बे दिनों की उक्त अवधि से अधिक हिरासत में रखने के विशेष कारण बताते हुए, उक्त अवधि को एक सौ अस्सी दिनों तक बढ़ाया जाता है।

(6) उपरोक्त प्रावधान बिल्कुल प्रावधान (बीबी) के समान है, जिसे आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (इसके बाद 'टीएडीए' के रूप में संदर्भित) की धारा 20 की उप-धारा (4) के खंड (बी) के बाद डाला गया था। . जितेंद्र विष्णु ठाकुर के मामले (सुप्रा) में प्रावधान (बीबी) प्रथम लोक सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचार के लिए आया था। उस सहजता में, यह माना गया कि यदि TADA की धारा 20 (4) (बी) के साथ पढ़ी गई संहिता की धारा 167 (2) के तहत प्रदान की गई अवधि के भीतर जांच पूरी नहीं होती है, तो जांच एजेंसी की डिफ़ॉल्ट के कारण निर्धारित अधिकतम अवधि के भीतर जांच पूरी करने में या

विस्तारित, जैसा भी मामला हो, जमानत पर रिहाई का आदेश प्राप्त करने के लिए आरोपी के पक्ष में एक अपरिहार्य अधिकार अर्जित होता है। जब आरोप पत्र निर्धारित या विस्तारित समय के भीतर दायर नहीं किया जाता है, तो आरोपी संहिता की धारा 167 के साथ पठित टीए डीए की धारा 20 की उपधारा (4) के तहत जमानत के लिए आवेदन करने का हकदार होगा। आरोपी के उक्त अधिकार को ध्यान में रखते हुए, उस मामले में यह माना गया कि जब लोक अभियोजक ने धारा (बीबी) के तहत समय विस्तार देने के लिए अदालत को रिपोर्ट सौंपी, तो अदालत को आरोपी को नोटिस जारी करना आवश्यक है। अभियोजन को विस्तार देने से पहले, ताकि अभियुक्त को उसके लिए उपलब्ध सभी वैध और कानूनी आधारों पर विस्तार का विरोध करने का अवसर मिल सके। इसे निम्नानुसार आयोजित किया गया था

> ''यह सच है कि पीएडी ए की धारा 20 की उप-धारा 4 के न तो खंड (बी) और न ही (बीबी) में विशेष रूप से ऐसे नोटिस जारी करने का प्रावधान है, लेकिन हमारी राय में ऐसे नोटिस जारी करने को इन प्रावधानों में पढ़ा जाना चाहिए। अभियुक्त और अभियोजन दोनों के हित के साथ-साथ दोनों पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता है और अभियुक्त या लोक अभियोजक को नोटिस जारी करना, जैसा भी मामला हो, इसके अनुरूप होगा। कार्रवाई में निष्पक्षता के साथ, जिसे अदालतों ने हमेशा प्रोत्साहित किया है और यहां तक कि इस पर जोर भी दिया है। यह एक ओर अभियुक्त की स्वतंत्रता के हित और दूसरी ओर अभियोजन एजेंसी के माध्यम से बड़े पैमाने पर समाज के बीच एक उचित संतुलन भी स्थापित करेगा। अधिनियम की योजना में अभियुक्त या लोक अभियोजक को इस तरह का नोटिस जारी करने पर कोई रोक नहीं है और किसी भी पक्ष को ऐसा नोटिस जारी करने से किसी भी तरह का कोई पूर्वाग्रह नहीं हो सकता है।.....

**XXX**

धारा 20 (4) के तहत जमानत देने के लिए एक आवेदन का निर्णय अभियोजन एजेंसी द्वारा गुण-दोष से प्रभावित हुए बिना जांच पूरी करने के लिए निर्धारित या विस्तारित अवधि के भीतर आरोप-पत्र दायर करने में चूक के लिए अपने गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। मामले की गंभीरता. यदि चालान दाखिल नहीं किया गया है, तो न्यायालय के पास किसी आरोपी को धारा 20 (4) के खंड (बी) द्वारा निर्धारित अवधि से अधिक या उक्त धारा के खंड (बीबी) के तहत विस्तारित अवधि से अधिक हिरासत में भेजने की कोई शक्ति नहीं है।

*(सतीश कुमार मित्तल, जे.)*

केवल इस आधार पर कि आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति का है या अपराध बहुत गंभीर है। टीएडीएटी की धारा 20 (4) के तहत जमानत देने पर विचार करने के लिए ये आधार अप्रासंगिक हैं

इस तरह के विस्तार को प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में, यह आगे देखा गया कि एडीए की धारा 20 की उप-धारा 4 के खंड (बीबी) को पढ़ने से पता चलता है कि विधायिका ने जांच पूरी करने के लिए समय के विस्तार की मांग करने का प्रावधान किया है। लोक अभियोजक की रिपोर्ट. टाई विधायिका ने जानबूझकर अदालत से समय विस्तार मांगने के लिए आवेदन करने का काम किसी जांच अधिकारी पर नहीं छोड़ा। लेकिन जब जांच निर्धारित समय के भीतर पूरी नहीं होती है और जहां जांच पूरी करने के लिए अधिक समय मांगना आवश्यक हो जाता है, तो जांच एजेंसी को सबसे पहले खुद को लोक अभियोजक की जांच के लिए प्रस्तुत करना होगा और उसे प्रगति के बारे में संतुष्ट करना होगा। जांच करें और किसी आरोपी की आगे की हिरासत की मांग करने के लिए कारण बताएं। यह माना गया कि लोक अभियोजक राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण अधिकारी है, लेकिन वह जांच एजेंसी का हिस्सा नहीं है। मैं यानी एक स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण है. लोक अभियोजक से अपेक्षा की जाती है कि वह जांच एजेंसी को जांच पूरी करने में सक्षम बनाने की दृष्टि से समय के विस्तार के लिए अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले स्वतंत्र रूप से जांच एजेंसी के अनुरोध पर अपना दिमाग लगाए। वह केवल डाकघर या अग्रेषण एजेंसी के रूप में कार्य नहीं करेगा। समय विस्तार मांगने के लिए जांच एजेंसी द्वारा दिए गए कारणों की जांच करना लोक अभियोजक का कर्तव्य है। वह जांच एजेंसी से असहमत हो सकता है और समय बढ़ाने के लिए अदालत में रिपोर्ट सौंपने से इनकार कर सकता है। इसे आगे इस प्रकार देखा गया

"इस प्रकार समयसीमा के विस्तार की मांग करने के लिए लोक अभियोजक को जांच एजेंसी के अनुरोध पर अपने दिमाग के स्वतंत्र आवेदन के बाद, नामित न्यायालय को एक रिपोर्ट देनी होगी जिसमें जांच की प्रगति का संकेत दिया जाएगा और रखने के लिए औचित्य का खुलासा किया जाएगा। जांच एजेंसी को जांच पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए आरोपी को आगे की हिरासत में रखा गया है। 'मैं लोक अभियोजक अपने अनुरोध या आवेदन और रिपोर्ट के साथ जांच अधिकारी के अनुरोध को संलग्न कर सकता हूं, लेकिन उसकी रिपोर्ट, जैसा कि खंड (बीबी) के तहत परिकल्पित है, को प्रथम दृष्टया खुलासा करना चाहिए, कि उसने अपना दिमाग लगाया है और था जांच की प्रगति से संतुष्ट हैं और जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय देना जरूरी समझा।

'Ilie uscofthc अभिव्यक्ति "सार्वजनिक अभियोजक की रिपोर्ट पर जांच की प्रगति और उक्त अवधि से परे आरोपी की हिरासत के विशिष्ट कारणों का संकेत" ▶ जैसा कि धारा की उप-धारा (2) में खंड (बीबी) में होता है 167 के रूप में

धारा 20 (4) द्वारा संशोधित एक आरोपी को अनुचित रूप से हिरासत में नहीं रखने और केवल लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर विस्तार देने के विधायी इरादे का महत्वपूर्ण और संकेतक है। इसलिए, लोक अभियोजक की रिपोर्ट [केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है क्योंकि

इसकी स्वीकृति के परिणाम आरोपी की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं और इसलिए, इसे खंड (बीबी) में निहित आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करना चाहिए। समय विस्तार के लिए एक जांच अधिकारी का अनुरोध लोक अभियोजक की रिपोर्ट का विकल्प नहीं है। जहां या तो खंड (बीबी) द्वारा परिकल्पित कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है या लोक अभियोजक द्वारा दायर की गई रिपोर्ट नहीं है

नामित न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, क्योंकि खंड (बीबी) के तहत समय विस्तार देना न तो औपचारिकता है और न ही स्वचालित है, आवश्यक परिणाम यह होगा कि एक आरोपी जमानत मांगने का हकदार होगा और अदालत उसे जमानत पर रिहा कर देगी यदि वह निर्दिष्ट न्यायालय द्वारा अपेक्षित जमानत प्रस्तुत करता है। यह केवल उस फॉर्म का प्रश्न नहीं है जिसमें खंड (बीबी) के तहत विस्तार का अनुरोध किया गया है, बल्कि सारगर्भित है। रिपोर्ट की सामग्री, लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत की जाएगी अपने

दिमाग का उचित उपयोग, नामित न्यायालय को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि क्या। विस्तार एक निश्चित सहजता से दिया जाना चाहिए। ध्यान में रखते हुए

किसी आरोपी को आगे की हिरासत में रखने के संबंध में विस्तार की मंजूरी के परिणाम, नामित न्यायालय को जांच पूरी करने के लिए समय का विस्तार देने के लिए, लोक अभियोजक की रिपोर्ट के औचित्य से संतुष्ट होना चाहिए। जहां नामित न्यायालय इस तरह के विस्तार को देने से इनकार करता है, अभियोजन पक्ष की 'चूक' के कारण जमानत पर रिहा होने का अधिकार अपरिहार्य हो जाता है और धारा 20 की उपधारा (4) में विचार किए गए कारणों के अलावा अन्य कारणों से पराजित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि चर्चा की गई है इस फैसले के पहले भाग में. हम श्री माधव रेड्डी या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री तुसली से सहमत होने में असमर्थ हैं, भले ही लोक अभियोजक जांच का अनुरोध 'प्रस्तुत' करता हो

अधिकारी द्वारा अदालत को भेजा गया, या जांच अधिकारी के अनुरोध को अदालत में 'अग्रेषित' किया गया, तो इसे लोक अभियोजक की रिपोर्ट माना जाना चाहिए। जब हम एक नागरिक की स्वतंत्रता के साथ काम कर रहे हैं तो आईटिक्रे के पास ऐसे निर्माण की कोई गुंजाइश नहीं है। अदालतों से अपेक्षा की जाती है कि वे उत्साहपूर्वक उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करें, खंड (बीबी) को बिना किसी अभिव्यक्ति को जोड़े या प्रतिस्थापित किए उसकी सरल भाषा में पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए। हमने पहले ही लोक अभियोजक की रिपोर्ट के महत्व पर विचार किया है और इस बात पर जोर दिया है कि वह न तो जांच एजेंसी का 'डाकघर' है और न ही इसकी 'अग्रेषण एजेंसी' है, बल्कि उस पर एक वैधानिक कर्तव्य लगाया गया है। उसे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर अपना दिमाग लगाना चाहिए और उसकी रिपोर्ट में पहली नजर में यह खुलासा होना चाहिए कि उसने धारा 20 की उप-धारा (4) के खंड (बीबी) में निहित जुड़वां शर्तों पर अपना दिमाग लगाया था। चूंकि, कानून के अनुसार उसे धारा द्वारा परिकल्पित तरीके से रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, इसलिए उसे धारा द्वारा प्रदान किए गए तरीके से ही कार्य करना होगा, किसी अन्य तरीके से नहीं। एक नामित न्यायालय जो एक वैध रिपोर्ट की आवश्यकताओं को नजरअंदाज करता है और अनदेखा करता है, वह अपने आवश्यक कर्तव्यों में से एक के प्रदर्शन में विफल रहता है और खंड (बीबी) के तहत अपने आदेश को कमजोर बनाता है। क्या लोक अभियोजक अपनी रिपोर्ट को एक रिपोर्ट के रूप में या विस्तार के लिए एक आवेदन के रूप में लेबल करता है, इसका तब तक कोई खास महत्व नहीं होगा जब तक कि यह इस तथ्य पर प्रदर्शित न हो जाए कि उसने अपना दिमाग लगाया है और जांच की प्रगति से संतुष्ट है और धारा (बीबी) (सुप्रा) द्वारा परिकल्पित किसी आरोपी को आगे की हिरासत में रखने के लिए विस्तार देने के कारणों की वास्तविकता, लोक अभियोजक द्वारा अपनी रिपोर्ट में जांच अधिकारी के आवेदन या अनुरोध के मात्र पुनरुत्पादन को प्रदर्शित किए बिना, जीवित रखती है। दिमाग लगाने और अपनी संतुष्टि दर्ज करने से, उसकी रिपोर्ट खंड (बीबी) द्वारा परिकल्पित के रूप में प्रस्तुत नहीं होगी और यह समय के विस्तार की मांग करने के लिए एक उचित रिपोर्ट नहीं होगी। उचित रिपोर्ट के अभाव में नामित न्यायालय के पास किसी आरोपी को जमानत पर रिहा होने के उसके अपरिहार्य अधिकार से इनकार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि यदि कोई आरोपी चाहता है और तैयार है तो निर्धारित समय के भीतर अभियोजन पक्ष द्वारा चालान दाखिल करने में चूक के कारण उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है। अदालत के निर्देशानुसार जमानत बांड प्रस्तुत करना। इसके अलावा, किसी आरोपी को हिरासत से आगे रखने के लिए कोई विस्तार नहीं दिया जा सकता है

> जांच को पूरा करने के लिए निर्धारित अवधि को छोड़कर और जैसा कि खंड (बीबी) के तहत कोई भी विस्तार दिए जाने से पहले ही कहा गया है, आरोपी को नोटिस दिया जाना चाहिए और उसे अपनी बात रखने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वह अनुदान पर आपत्ति जता सके। विस्तार।"

माननीय उच्चतम न्यायालय ने संजय दत्त मामले (सुप्रा) में फिर से TADA की धारा 20 (4) के खंड (बीबी) के दायरे पर विचार किया। जांच पूरी करने के लिए समय विस्तार देने से पहले आरोपी को नोटिस जारी करने की आवश्यकता को थोड़ा संशोधित किया गया था और इसे निम्नानुसार देखा गया था: -

> "TADA अधिनियम की धारा 20 (4) (बीबी) के तहत केवल आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (1) के अनुसार आरोपी को अदालत के समक्ष पेश करने की आवश्यकता होती है और इस तरह से आगे की मोहलत देने से पहले आरोपी को नोटिस की आवश्यकता होती है। TADA अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (4) के खंड (बीबी) के अतिरिक्त प्रावधान के अनुसार 180 दिनों की निर्धारित अवधि को हितेंद्र विष्णु ठाकुर मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले में समझा जाना चाहिए। जांच पूरी करने के लिए विस्तार देने से पहले आरोपी को इस तरह के नोटिस की आवश्यकता आरोपी को कारण बताने वाला लिखित नोटिस नहीं है। उस समय अभियुक्त को अदालत में पेश करके यह सूचित करना कि जांच पूरी करने की अवधि बढ़ाने के सवाल पर विचार किया जा रहा है, पनपॉस्क के लिए अकेले ही पर्याप्त है।"

(7) प्रतिवादी के विद्वान वकील ने न तो उपरोक्त कानूनी स्थिति का खंडन किया और न ही किसी विपरीत निर्णय का हवाला दिया।

(8) यह स्वीकार किया गया है कि 9.5.2012 को, जब एनआईए, विशेष न्यायालय द्वारा जांच पूरी करने का समय बढ़ाया गया था, तो न तो आरोपी उपस्थित था और न ही जांच एजेंसी द्वारा समय विस्तार की मांग करते हुए दायर आवेदन पर कोई नोटिस जारी किया गया था। वह या उसका वकील। आक्षेपित आदेश से यह भी स्पष्ट है कि समय विस्तार के लिए आवेदन इंस्पेक्टर आरएस जंबवाल के माध्यम से दायर किया गया था, जिस पर लोक अभियोजक ने भी हस्ताक्षर किए थे। लेकिन न तो आवेदन और न ही आक्षेपित आदेश यह दर्शाता है कि लोक अभियोजक ने अपने दिमाग का उचित उपयोग करने के बाद और जांच की प्रगति के बारे में संतुष्ट होने के बाद उक्त आवेदन दायर किया। हालांकि यूए (पी) अधिनियम की धारा 43- डी (2) (बी) का प्रावधान पहले विचार के लिए नहीं आया है

किसी भी अदालत में, लेकिन निर्विवाद रूप से, ये प्रावधान टाडा की धारा 20 की उपधारा (4) के खंड (बीबी) के लिए प्रासंगिक हैं, जिस पर उपरोक्त दो निर्णयों में प्रथम आयनब्लक सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचार किया गया है। इसलिए, इन दो निर्णयों में दी गई व्याख्या यूए (पी) अधिनियम की धारा 43-डी (2) (बी) के प्रावधान पर पूरी तरह लागू होगी।

(9) वर्तमान मामले में आरोपी को नोटिस जारी करने की अनिवार्य आवश्यकता का पालन नहीं किया गया। यहां तक कि 9.5.2012 को, जब जांच एजेंसी द्वारा जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए आवेदन दिया गया और अनुमति दी गई, तब भी आरोपी उपस्थित नहीं था। इसलिए, उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था, जैसा कि संजय दत्त के मामले में बताया गया है। जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने से पहले आरोपी को उक्त प्रार्थना का विरोध करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ। 'आक्षेपित आदेश से अभियुक्त पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, क्योंकि समय बढ़ाने से जमानत पर

रिहाई का आदेश लेने का उसका अपरिहार्य अधिकार खत्म हो रहा था। जैसा कि उपरोक्त निर्णयों में दर्शाया गया है, लोक अभियोजक के माध्यम से आवेदन को आगे बढ़ाने और लोक अभियोजक की रिपोर्ट दाखिल करने की अन्य आवश्यकताओं का भी अनुपालन नहीं किया गया है।

(10) उपरोक्त के मद्देनजर, हमारी राय है कि एनआईए, विशेष अदालत, पंचकुला द्वारा पारित आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि यह आरोपी को कोई नोटिस दिए बिना या उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना पारित किया गया था। नतीजतन, एनआईए, विशेष अदालत, पंचकुला द्वारा पारित दिनांक 9.5.2012 के आदेश को रद्द कर दिया गया है और मामले को जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने के लिए अभियोजन पक्ष की प्रार्थना पर विचार करने और निर्णय लेने के निर्देश के साथ उक्त अदालत को भेज दिया गया है। अपने पूर्व आदेश से प्रभावित हुए बिना दस दिन के अंदर स्पीकिंग ऑर्डर पारित कर आरोपी कमल चौहान को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया। वर्तमान सहजता के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और न्याय के हित में, हम आवेदन के नए निर्णय तक जांच पूरी करने की अवधि दस दिनों के लिए बढ़ाते हैं।

(11) रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति तुरंत एनआईए, विशेष अदालत, पंचकुला को भेजे।

(12) तदनुसार, अपील का निपटारा किया जाता है।

**एम जैन**

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जितेश कुमार शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

झज्जर, हरियाणा